एडवोकेट माही यादव, जिनकी PIL ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों में खोला एडमिशन का रास्ता

आज का जो बहरोड़-कोटपूतली जिला है उसका कोटपूतली उस समय जयपुर जिले में ही हुआ करता था। इसी कोटपूतली का एक गांव है भैंसलाना। ये वही भैंसलाना गांव है जिसके काले संगमरमर की पहचान पूरे देशभर में है। मगर आज के समय में गांव की पहचान फिर सुर्खियों में है। जी हां, राष्ट्रीय फलक पर इस चर्चा का कारण है गांव की बेटी एडवोकेट माही यादव जो अपनी काबिलियत के दम पर वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता बनी हैं। एडवोकेट माही यादव अपनी साफगोई के लिए जानी जाती हैं और इसी अंदाज में सरकार का पक्ष रखती नजर आती हैं। अनुशासन के प्रति बेहद ही सख्त मिजाज रखने वाली माही के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू उनका सरल, सौम्य एवं सुलभ होना भी है। आज **''तोड़ों बेड़ियाँ, कम नहीं बेटियाँ''** की खास सीरीज़ में हम जानेंगे कि एडवोकेट माही यादव पर क्यूँ पूरे समाज को नाज होना लाजिमी है।

तारीख़ 07 जुलाई वर्ष 1982 का दिन. गांव के किसान बी. आर. यादव के यहां एक बिटियां जन्म लेती है. नाम रखा जाता है माही. किसान पिता अपनी बेटी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखते हैं या कहें की पालन-पोषण में बेटा-बेटी का भेद कभी नहीं रखा। बेटों के साथ बिटियां को भी स्कूल में दाखिला दिलवाया जाता है। बेटी माही जब अच्छे नंबरों से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो घोड़ी पर बैठाकर शोभायात्रा निकाली जाती है। उसकी हौंसला अफ़जाई के इस अंदाज से समाज को बेटियों के प्रति धारणा बदलने के लिए ख़ास संदेश भी दिया गया। उस वक्त तो शायद ही किसी को यह भान होगा कि यह बेटी आगे चलकर पूरे गांव का ही नाम रोशन करेगी। अपनी शुरुआती शिक्षा गांव से पूरी करने के बाद माही आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर आती है। माही राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलएलबी पास आउट है। कॉलेज के दिनों में माही छात्र हितों के कार्यों में काफी मुखर रही है।

● माही हैं कॉर्पोरेट लॉयर, जस्टिस समीर जैन के चैम्बर से शुरू की थी प्रैक्टिस

एडवोकेट माही यादव राजस्थान हाईकोर्ट की जानी-मानी कॉर्पोरेट लॉयर हैं। माही ने अपनी वकालत की शुरुआत दिग्गज कॉर्पोरेट एडवोकेट समीर जैन के चैम्बर से की थी। बता दें कि वर्तमान में समीर जैन राजस्थान हाईकोर्ट में सीनियर जज हैं। अनुशासन और साफगोई की बात पर माही कहती हैं कि परिवार के बाद मैंने यह सब अपने गुरु समीर जैन साहब से ही सीखा है।

● माही की जनहित याचिका और लड़कियों को मिलने लगा सैनिक स्कूलों में दाखिला

माही जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तब एक रोज अखबार में ऐसा ऐड देखती हैं जो लैंगिक भेदभाव को दर्शाता था। विज्ञापन सैनिक स्कूल में एडमिशन को लेकर था लेकिन वहां जो एक लाइन लिखी थी उसने माही को मानसिक रूप से झकझोर दिया। वह लाइन थी-ओनली फोर बॉयज। माही कहती हैं कि मेरे परिवार से कई पीढ़ियों के लोग भारतीय सेना में रहकर देश सेवा करते आये हैं और मैं उन सभी से सैनिक स्कूल और नेशनल मिलिट्री स्कूल में लड़कियों के एडमिशन नहीं होने की टीस के साथ ही इसकी संभावनाओं के बारे में बात करती रहती थी। कुछ सालों बाद एक सुबह फिर माही की नजर में ऐसा ही विज्ञापन आ जाता है। इस बार माही ठान लेती है कि अब वह चुपचाप नहीं बैठने वाली है। क्यूँकि अब माही वकील बन चुकी थी। अब माही पर महिला अधिकारों की जानकारी के साथ लैंगिक भेदभाव को खत्म करवाने का जज्बा सवार हो चुका था। वर्ष 2016 में एडवोकेट माही ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला दिये जाने एवं इस तरह के लैंगिक भेदभाव को खत्म किये जाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिला की। कोर्ट ने इस पीआईएल पर केंद्र सरकार को आदेश देकर पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। माही की यह कानूनी लड़ाई रंग लाई और इस तरह सैनिक स्कूलों में लड़कियों के एडमिशन की राह खुली।

● लोगों के चेहरों की खुशी देती है सच्चा सुकून

एडवोकेट माही यादव कहती हैं कि लोगों के चेहरों की खुशियां ही उन्हें सच्चा सुकून देती हैं। यह सब संस्कार पारिवारिक विरासत में मिलना बताती है। माही कहती हैं कि उन्हें पब्लिक इश्यूज पर काम करना पसंद है। इसके लिए इन्हें दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। माही लोगों के खिले चेहरों को ही अपनी सबसे बड़ी फीस मानती हैं और नेकदिली को ही अपना फर्ज।

● निराली है देशप्रेम की भावना

माही की देशप्रेम की भावना भी अजब है। माही कहती हैं कि यूँ तो मुझे सिर्फ खूब पढ़ने का ही शौक है लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ है तो वह है राष्ट्रगान गाना-सुनना। माही बताती है कि उस समय मैं सिर्फ 5-6 कक्षा में हुआ करती थी जब हमारे घर में पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया। परिवार के सभी लोग एक साथ समाचार देखते और रात 10.30 बजे आने वाला सीरियल परमवीर चक्र। परिवार के लोग भारतीय सेना में रहकर देशसेवा कर रहे थे ऐसे में देशप्रेम की भावना तो संस्कारों में ही मिली है लेकिन परमवीर चक्र सीरियल से राष्ट्रगान ने बालमन पर ऐसी जगह बना ली जो कि हमेशा के लिए अमिट रहेगी। माही सिर्फ इसलिए

क्रिकेट मैच या फिल्में देखती हैं कि दोनों के शुरू होने से पहले दर्शकों द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान होता है तो उन्हें एक ही समय में करोड़ों लोगों द्वारा देखा-सुना जाता है और देशप्रेम की लौ एक साथ लोगों के दिलों में धड़कती है।

● जानवरों के प्रति दयालुता ऐसी की गाड़ी में लेकर घूमती हैं उनके लिए खाना-पानी

एडवोकेट माही यादव की जानवरों के लिए दयालुता कुछ ऐसी है कि उनके लिए खाना-पानी गाड़ी में लेकर ही घूमती हैं। छोटू (वह दूधमुहां पिल्ला जो बचपन में ही अपनी मां से बिछड़ गया था या उसे हमेशा के लिए खो दिया था) और सुनहरी इनके परिवार के अभिन्न अंग बन चुके हैं। जिस आवासीय सोसायटी में माही रहती हैं वहां नीचे ऐसे ही बेजुबान भूखे-प्यासे जानवरों के लिए खाना-पानी की व्यवस्था करके रखती हैं। इनके लिए माही कहती हैं कि लोग कहते है कि जानवर बोलते नहीं हैं लेकिन ये बोलते भी हैं और समझते भी हैं बस हमें इन्हें समझना आना चाहिए।

● राष्ट्रीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं में कानूनी जागरूकता वाले आलेख होते हैं प्रकाशित

एडवोकेट माही यादव लोगों को अपने अधिकारों को जानने के लिए कहती हैं। इसके लिए इनके द्वारा बहुत कुछ लिखा भी जाता है। कानूनी जानकारी देने वाले इनके आलेख देश के राष्ट्रीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं जो कि आमजन के साथ ही कानूनी पढ़ाई वाले छात्रों के लिए बहुत ही मददगार होते हैं।

RAJHIN/2021/86331

द कलंदर पोस्ट

साप्ताहिक

वर्ष.03 | अंक: 46 | जयपुर, रविवार 14 जुलाई, 2024 | पृष्ठ-8 | मूल्य: 10 रूपए प्रति

पुतिन ने मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया

पीएम की रूसी राष्ट्रपति को सलाह- युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, वार्ता जरूरी

रूस। मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। ये सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। इससे पहले मोदी दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। पीएम की इस बात के जवाब में पुतिन ने कहा, आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम उसके लिए आपके आभारी हैं। पीएम ने बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है।

मोदी रूस में 26 घंटे रहे, पुतिन के साथ 8 घंटे बिताए -मोदी ने दो दिवसीय दौरे पर रूस में 26 घंटे बिताए। इस दौरान पुतिन के साथ 7-8 घंटे रहे। दोनों नेताओं ने औपचारिक और अनौपचारिक चार मीटिंग कीं। प्राइवेट डिनर करने के अलावा उन्होंने साथ में लंच भी किया। रूसी राष्ट्रपति ने मोदी को गोल्फ कार्ट में घुमाया।

शिखर वार्ता में मोदी की 4 बड़ी बातें...

- पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है। इसलिए मॉस्को में हुए आतंकी हमले का दर्द समझ सकता हूं। मैं हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता हूं।
- शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। शांति के लिए मेरे मित्र पुतिन की बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी है। मैं विश्व समुदाय को आश्वत करना चाहता हूं कि भारत शांति का पक्षधर है।
- चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हों, जब जान का नुकसान होता है तो मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को दुख होता है।
- जब मासूम बच्चों की हत्या होती है, जब हम मासूम बच्चों को मरते देखते हैं तो दिल दहल जाता है।

कृषक हितैषी बजट के लिए प्रदेशभर से आए किसानों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

देश में सर्वाधिक शासन करने वालों ने नहीं की किसान की चिंता : मुख्यमंत्री

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं। करोड़ों देशवासियों का पेट भरने के साथ ही वे देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तित बजट-2024-25 में कृषि संबंधी ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए किसानों द्वारा अभिनन्दन और आभार समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी किसानों को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। हमने सरकार का गठन होते ही पूर्वी राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण ईआरसीपी योजना के लिए केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार के साथ ऐतिहासिक समझौता किया। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए यमुना जल समझौते को भी मूर्त रूप दिया, जबकि पूववर्ती सरकार ने इस संबंध में केंद्र और हरियाणा सरकार से कभी पत्र व्यवहार तक नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपए करने तथा गेहूं की एमएसपी बढ़ाने तथा पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण देने जैसे निर्णय हमारी किसान एवं पशुपालक हितैषी नीति का प्रतीक हैं।

25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित

केंद्र सरकार का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली(एजेंसी)। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। शाह ने लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया।

पीएम ने इसे काला दौर बताया, कांग्रेस बोली- एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, '25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और

भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। ये भारत के इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। उधर, कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 'यह नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है, जिसने दस साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उसे 4 जून, 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार दी- जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा।

राजीव दत्ता फिर बने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के ओएसडी

नई दिल्ली। वरिष्ठ आरपीएस अधिकारी राजीव दत्ता को एक बार फिर से लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का ओएसडी बनाया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारें में आदेश जारी किया है। राजीव दत्ता लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के पिछले कार्यकाल में भी OSD रहे हैं।

कोटा से ही ताल्लुकात रखते हैं राजीव दत्ता -वरिष्ठ आरपीएस अधिकारी राजीव दत्ता की पहचान एक कुशल प्रशासक की है। कार्य के प्रति बहुत सख्त मिजाज रखने वाले दत्ता को उनका सरल, सुलभ एवं सौम्य व्यवहार खास बनाता है। वर्ष 2003 बैच के RPS अधिकारी राजीव दत्ता जयपुर विकास प्राधिकरण, आबकारी, इंटेलिजेंस, पर्यटन विभाग में अहम पदों के अलावा जयपुर नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर विजिलेंस के पद पर रहते हुए अपनी प्रशासनिक कुशलता का लोहा मनवा चुके हैं।

अगली सदी में भी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा भारत-यूएन

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। भारत अगली सदी में भी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के मध्य में चरम पर होगी, लेकिन इसके बाद इसमें धीरे-धीरे गिरावट शुरू होगी। इसके बाद भी भारत अगली सदी (2100) में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। वरिष्ठ जनसंख्या मामलों की अधिकारी क्लेयर मेनोजी ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत इस समय जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अनुमान है कि यह पूरी शताब्दी में ऐसा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के आसपास चरम पर होगी। फिर इसमें थोड़ी गिरावट आनी शुरू होगी। सदी के अंत तक भारत की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब रहने का अनुमान है।

विधान सभा में सदस्यों के लिए फास्ट टैग शिविर स्पीकर ने किया शुभारम्भः एक ही स्थान पर समस्त सुविधाःदेवनानी

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को यहां विधान सभा में विधायकों के लिए लगाये गये चार दिवसीय फास्ट टैग शिविर का शुभारम्भ किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस शिविर में विधान सभा सदस्यों को फास्ट टैग बनाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अध्यक्ष देवनानी की पहल पर विधान सभा में लगाये गये इस शिविर से विधायकों को एक ही स्थान पर फास्ट टैग से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। देवनानी ने कहा कि विधायकों के लिए फास्ट टैग के लिए एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। फास्ट टैग का यह शिविर शुक्रवार 12 जुलाई,

सोमवार 15 जुलाई और मंगलवार 16 जुलाई तक प्रातः 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक यह शिविर आयोजित किया गया है। राज्य में विधायकगण के लिए टोल छूट फास्ट टैग जारी किया जायेगा और अन्य राज्य के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोग के लिए वॉलेट में बैलेंस रखा जाना आवश्यक होगा। शिविर में विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पहुँचने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक श्री हर्षित पारीक ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। विधान सभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, शिविर संचालन प्रभारी के.के. शर्मा, प्राधिकरण के सुरेश सैनी, किशन गोपाल और विनोद मौजूद थे।

सम्पादकीय...

भारत-रूस मित्रता को जीवंतता देने का सार्थक प्रयास

भारत-रूस की मैत्री को नये आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति पुतिन ने न केवल मैत्री के धागों एवं द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती दी है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को नये शिखर देने का प्रयास किया है। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के लिये एक नए सोच के साथ नये सफर का आगाज है। एक ऐसे समय में, जबकि यूक्रेन-रूस युद्ध को पश्चिमी देशों के विरोध के कारण रूस दुनिया में अलग-थलग है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहले विदेश यात्रा के लिये रूस का चयन करके जता दिया है कि भारत-रूस की मैत्री अक्षुण्ण है और किसी भी तरह के दुनिया के दबाव में यह दोस्ती कमजोर नहीं पड़ने वाली है। भारत ने जहां मैत्री को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में उल्लेखनीय उपक्रम किये हैं, वहीं अपने मित्र देश को युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में अपना स्पष्ट रुख भी जताया है। मोदी की इस यात्रा की एक बड़ी निष्पत्ति यह है कि रूस में अब दो नये वाणिज्यिक दूतावास खुलने जा रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियां तेजी से एवं ज्यादा बढ़ेगी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस रूस यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों ने विरोध जताया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत के लिए रूस की मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपने मैत्री-मूल्यों को किसी भी दबाव में कमतर नहीं होने देगा। भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस यात्रा पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसे शांति प्रयासों को झटका तक बता चुके हो या अमेरिका ने भी यात्रा को लेकर अपनी चिंता जता दी हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी युद्ध विरोधी सोच के चलते ही यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस नहीं गए थे। दोनों देशों के बीच होने वाली सालाना द्विपक्षीय शिखर बैठक भी 2022 के बाद से नहीं हो पाई थी। इससे रूस के कुछ हलकों में यह धारणा बनने लगी थी कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव में रूस से दूरी बनाए रखना चाहता है। दुनिया में बन रही इस नई धारणा को तोड़ना जरूरी था, इसी दृष्टि से इस यात्रा के पीछे जहां द्विपक्षीय रिश्तों को संदेहों और अविश्वासों से मुक्त करने का ध्येय था, वहीं अंतरराष्ट्रीय हलकों में यह स्पष्ट संदेश भेजना था कि भारत को किसी तरह के दबाव के जरिए इस या उस पक्ष में झुकाना संभव नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में इसका जिक्र किया कि उनके रूस आने पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। दुनिया भर में इस यात्रा को गहरी उत्सुकता से देखा जा रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखें तो यह कोई अचरज वाली बात भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का जोर इस बात पर रहा है कि भारत रूस से अपनी करीबी खत्म करे। भारत अब एक स्वतंत्र ताकत है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, बड़े शक्तिशाली देशों के लिये भी भारत एक बाजार है। इसलिये भारत किसी भी दबाव में न आते हुए शुरू से ही यह स्पष्ट कर रखा है कि वह अपने राष्ट्रहित पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा।

सावन में कावड़ का जल कहां से लेना चाहिए? किस दिन शिवजी का जलाभिषेक करने से पूरी होती है मनोकामना

सावन में कावड़ का जल कहां से लेना चाहिए? किस दिन शिवजी का जलाभिषेक करने से पूरी होती है मनोकामना सावन में कावड़ यात्रा की जाती है। कावड़िये देश के प्रसिद्ध घाटों से गंगाजल भरकर लाते हैं और फिर भगवान शिव का जलाभिषे करते हैं। जानें कावड़ में कहां से उठाया जाता है जल और किस दिन करते हैं जलाभिषेक-

सावन में की जाती है कावड़ यात्रा-भगवान शिव का अतिप्रिय माह सावन 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है जो कि 19 अगस्त को समाप्त होगा। सावन में शिव भक्त कावड़ लेकर जल लेने जाते हैं और उस जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। जानें कावड़िये कहां से लाते हैं जल और कब भगवान शिव पर चढ़ाना होता है शुभ-

सावन में कहां-कहां जल उठाते हैं-

सावन मास में कावड़िये देश के प्रसिद्ध घाटों से गंगाजल भरकर लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड से गंगा जल भर भगवान शंकर का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

कावड़ यात्रा का महत्व-

हिंदू धर्म में प्राचीन काल से कावड़ यात्रा चली आ रही है। सावन महीने में कावड़ यात्रा की जाती है। इस समय शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगाजल भर लाते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं।

किसने की थी कावड़ यात्रा की शुरुआत-

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सबसे पहली बार भगवान परशुराम गढ़मुक्तेशर के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। उसके बाद से ही कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष ग्रहण किया था, जिससे उनके शरीर में जलन हो गई थी, इसलिए भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है।

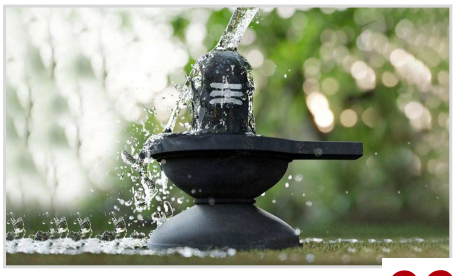

इस दिन जलाभिषेक करना माना जाता है बहुत शुभ-सावन में शिवरात्रि का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस साल सावन शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 को है। मान्यता है इस भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं।

महाकाल मंदिर के चौंकाने वाले रहस्य,क्यों उज्जैन में कोई राजा रात नही रुकता-सावन के महीने में मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी यानी उज्जैन में भक्तों तांता लगने वाला है। मंदिर सदियों पुराना है और इस मंदिर के कुछ रहस्य हैं जो आज भी चौंकाने वाले हैं। भगवान शिव का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां बाबा का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति जन्म मरण से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है।

कोई राजा यहां नहीं रुकता एक रात-महाकाल की नगरी उज्जैन में रात में कोई राजा नहीं रुकता। ऐसा कहा जाता है कि यहां के राजा महाकाल हैं। जो राजा यहां रुकता है, उसका राजपाठ सब नष्ट हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इन बातों का कितना आधार है, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी अभी यहां आप इन बातों को सुन सकते हैं। महाकाल के अलावा केवल विक्रमादित्य ही ऐसे राजा थे जो उज्जैन में रात विश्राम किए हैं। इसके अलावा किसी राजा ने यहां रात नहीं बताई है।

भगवान शिव की भस्म आरती क्यों, क्या है मान्यता-मान्यता के अनुसार दूषण नाम के एक राक्षस के कारण अवंतिका में आंतक हुआ करता था।नगर के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह नष्ट हो जाए, इस पर भगवान ने उसको भस्म कर दिया है और उसकी राख से अपना श्रृंगार कर लिया। इसके बाद शिवजी वहीं महाकाल के रूप में बस गए।

कहीं आप तो भी नहीं खाते शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिवजी से जुड़ी है कथा

शास्त्रों में शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद का सेवन करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते समय शिवजी के भक्त को कुछ खास बातों और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सावन मास भगवान भोलेनाथ की पूजा-आराधना करने के लिए उत्तम समय माना जाता है। इस महीने में महिलाएं और कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार का व्रत रखती है। पंचांग के अनुसार, इस साल सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो रही है और इसका समापन 19 अगस्त को इसका समापन होगा। सावन महीने में शिव पूजन के दौरान भोलेनाथ को भोग के रूप में फल, फूल समेत कई प्रकार के खाद्य पदार्थ चढ़ाएं जाते हैं। ऐसा करने बेहद शुभ फलदायी भी माना गया है। लेकिन मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुए भोग का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही इसे घर पर ले जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद के सेवन करने की क्यों मनाही होती है?

शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए?

शिवपुराण में शिव पर प्रसाद चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनचाही मुरादें पूरी करते हैं। ऐसा करने से जातक से जाने-अनजाने में हुई पापों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति को सभी रोग-दोषों से राहत मिलती है। शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। हालांकि, पौराणिक कथाओं के अनुसार, शिवजी के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। चंडेश्वर को भूत-प्रेतों का प्रधान माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने की मनाही होती है। माना जाता है कि शिवलिंग का प्रसाद चंड़ेश्वर यानी भूत-प्रेतों के लिए होता है। खासतौर पर साधारण पत्थर, चीनी मिट्टी और मिट्टी से बने शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ऐसे प्रसाद को आप खाने के बजाए नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा तांबे, सोने, चांदी, पारद समेत धातुओं से बने शिवलिंग पर चढ़ा हुए प्रसाद का सेवन किया जा सकता है। इन धातुओं से बनी शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाने से कोई दोष नहीं लगता है और आप इसे घर भी ले सकते हैं। वहीं, शिवजी की प्रतिमा पर चढ़े प्रसाद का सेवन करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है।

शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने के नियम =

शिवलिंग पर तुलसी दल और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए।

प्रसाद हमेशा पीतल या चांदी के धातु के पात्र में रखकर भोग लगाएं।

कभी भी भोग जमीन पर रखकर नहीं चढ़ाना चाहिए।

पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को भगवान के पास से उठा लें।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

जीवित्पुत्रिका या जितिया व्रत कब है? जानें शुभ मुहूर्त, पूजन विधि व महत्व

जीवित्पुत्रिका व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व पूरी रात निर्जला रहती हैं। जानें इस साल कब है जितिया व्रत- हिंदू धर्म में जीवित्पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को जितिया या जिउतिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जितिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ ग्रहण नहीं करती हैं। जानें इस साल कब है जीवित्पुत्रिका व्रत व पूजन का शुभ मुहूत-

जीवित्पुत्रिका या जिउतिया व्रत कब है- हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 38 मिनट से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर समाप्त होगी। इस साल जीवित्पुत्रिका व्रत 25 सितंबर 2024 को है।

जीवित्पुत्रिका व्रत का नहाय-खाय कब होगा-

24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाय खाय होगा और 25 सितंबर को निर्जला व्रत माताएं रखेंगी। इसके बाद 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा।

जीवित्पुत्रिका व्रत का महत्व- मान्यता है कि जितिया व्रत से संतान को लंबी आयु व खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को सुखों की प्राप्ति होती है।

जितिया व्रत पूजन के शुभ मुहूत-

लाभ - उन्नति- 06.10 ए एम से 07.41 ए एम

अमृत - सर्वोत्तम- 07.41 ए एम से 09-11 ए एम

शुभ - उत्तम- 10.41 ए एम से 12-12 पी एम

लाभ - उन्नति- 04.43 पी एम से 06-13 पी एम

जितिया व्रत पूजा- विधि-

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें

स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं।

धूप, दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं।

मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं।

कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप-दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें।

विधि- विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें।

बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक

बजट घोषणाओं को समय से धरातल पर उतारने का एक्शन प्लान तैयार:मुख्यमंत्री

जयपुर(नि.सं.)। विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 प्रस्तुत किए जाने के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं का तेजी के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का एक्शन प्लान बताया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रभारी सचिव 12 जुलाई को दोपहर से अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को चिन्हित करेंगे। साथ ही, भूमि चिन्हीकरण और आवंटन को गति देने का भी काम करेंगे। प्रभारी मंत्री 14 जुलाई को जिलों में प्रभारी सचिवों के साथ इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जनकल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संभावित बाधाओं को तत्काल दूर कर बजट घोषणाओं को समय से धरातल पर उतारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से संबंधित कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहना चाहिए ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री हर 15 दिन के अंतराल पर अपने विभाग की बजट घोषणाओं पर हुई प्रगति की विभागीय स्तर पर समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार विलम्ब नहीं हो, क्योंकि इससे लागत में वृद्धि होती है। उन्होंने विकास कार्यों के लिए भूमि आवंटन में तेजी लाने, लंबित भर्तियों की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने सहित अन्य जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित मंत्रिगण ने बैठक में बजट घोषणाओं की त्वरित क्रियान्विति और रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्रीगण, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

परीक्षण समिति की बैठक का हुआ आयोजन

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता एवं अंडर ट्रायल परीक्षण समिति की बैठक का हुआ आयोजन

जयपुर(नि.सं.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश की अध्यक्षता में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता के तहत अधिवक्तागण को देय मानदेय एवं अण्डर ट्रायल परीक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पल्लवी शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय ने बताया कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान में दिए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों की पालना में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कुल 32 प्रार्थना-पत्र रखे गए जिन पर कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यगण द्वारा विचार-विमर्श पर प्रतिकर राशि/अवार्ड पारित किए गए। मीटिंग के दौरान पीड़ित प्रतिकर में कुल 14 लाख 25000 राशि का अवार्ड पारित हुआ। इसी के साथ विधिक सहायता के तहत नियुक्त अधिवक्तागण के देय मानदेय के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिवक्तागण को नियमानुसार देय मानदेय के ऑर्डर जारी किए गए। साथ ही अंडर ट्रायल बंदी जो विभिन्न कैटेगरी में कारागार में निरुद्ध है उनकी रिहाई की अनुशंसा कर संबंधित न्यायालयों को भेजे जाने के निर्देश एवं आदेश प्रदान किए। बैठक में अनीष दाधीच, न्यायाधीश श्रम न्यायालय क्रम सं.01, जयपुर महानगर द्वितीय, श्री शिव कुमार, न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम सं. 1, जयपुर महानगर द्वितीय, सुश्री मांडवी राजवी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय, सुश्री राशि डोगरा डूडी, पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर उत्तर, श्री अमित कुमार, पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर पश्चिम, श्री पवन शर्मा, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, श्री संत कुमार जैन, लोक अभियोजक, श्री राकेश मोहन, अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर उपस्थित रहे।

मेवाड़ के कृष्णधाम सांवलिया जी

सांवलिया सेठ के भंडार से निकले रिकॉर्ड 19.76 करोड़ रुपए: एक महीने की सबसे ज्यादा राशि

चित्तौड़गढ़(वि.सं.)। मेवाड़ के कृष्णधाम सांवलिया जी के भंडार से निकली दान राशि की पूरे पांच राउंड में गिनती पूरी हो गई। जून महीने में भंडार और ऑनलाइन माध्यम से कुल 19 करोड़ 7 लाख 63 हजार 755 रुपए मिले। यह भंडार से निकली किसी भी एक महीने में सबसे ज्यादा राशि है। गुरुवार को 12 लाख 8 हजार 284 रुपए गिने गए। सोने-चांदी का तौल बुधवार को ही हो गया था। भंडार में चढ़ावे के 15 करोड़ 58 लाख 50 हजार 284 रुपए मिले। जबकि ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से लगभग 3 करोड़ 49 लाख 13 हजार 471 रुपए मिले थे। मंदिर मंडल के अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर ने बताया- चार जुलाई को भंडार खोला गया था। पहले दिन की गिनती के बाद तीन दिनों तक काउंटिंग नहीं हुई थी। पहली बार एक महीने में 19 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। बुधवार को सोने-चांदी का तौल हुआ था। इसमें कुल 505.5 ग्राम सोना और 88 किलो 877 ग्राम चांदी प्राप्त हुई। काउंटिंग के दौरान मंदिर मंडल के अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर, सदस्य संजय कुमार मंडोवरा, भैरूलाल सोनी, अशोक शर्मा, श्रीलाल पाटीदार, ममतेश शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी घनश्याम जरवाल, कार्य वाहक प्रशासनिक अधिकारी सेकेंड लहरी लाल मौजूद थे।

प्लास्टिक कारोबारी ने ऊंटों पर निकाली बेटे की बारात

अफ्रीका-कर्नाटक में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट;15 किलोमीटर के सफर में 15 ऊंटगाड़ी, 40 कारें निकलीं

जालोर(वि.सं.)। जालोर के बड़े प्लास्टिक कारोबारी ने बेटे की बारात ऊंटों पर निकालकर मैसेज दिया कि कल्चर सबसे पहले है। कारोबारी की अफ्रीका और (मैसूर) कर्नाटक में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट हैं। बारात 15 किलोमीटर तक निकाली गई। इसमें सजी धजी ऊंट गाड़ियों पर लाल गुमटियां बनाई थीं, बाराती सफेद परंपरागत पोशाक और लाल पगड़ी में थे। इसे देख हर कोई हैरान रह गया। मामला जालोर जिले के सायला उपखंड के बावतरा गांव का है। दूल्हे के चाचा सूरज देवासी ने बताया- परिवार का फोकस समाज के रीति-रिवाज को अच्छे से निभाने पर रहा। हमारी कोशिश है कि हम परंपरागत संस्कृति को जीवित रखें। भतीजे (दूल्हा) विक्रम की शादी सम्पन्न हुई है।

14 सूत्रीय मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की

सरपंच संघ की मांगों का उच्च स्तरीय परीक्षण कराने के निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार ने सरपंच संघ की मांगों का उच्च स्तरीय परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने पंचायती राज, मनरेगा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ सरपंच संघ की 14 सूत्रीय मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। सरपंच संघ की प्रमुख मांग है कि वर्ष 2022-23 व 2023-24 की राज्य वित्त आयोग मद की बकाया अनुदान राशि लगभग 3 हजार 4 सौ करोड़ रुपए उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके।इसी प्रकार मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मेड व कारीगरों के मानदेय में वृद्धि की जाय।मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान है उसे ऑफलाइन की जाय।जलजीवन मिशन हर घर में जल वितरण हेतु योजनाओं के संचालन व संधारण का उत्तरदायित्व जलदाय विभाग को देने की मांग की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राशि की मांग से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजने एवं अन्य प्रस्तावों का परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

घर में प्लांट लगाकर छाप रहा था नकली नोट, गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर युवाओं को जोड़ा; पूरे राजस्थान में करता था सप्लाई

जोधपुर (वि.सं.)। जोधपुर की सरदारपुरा पुलिस ने प्रदेश में नकली नोट सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने घर पर नकली नोट का पूरा प्लांट बना रखा था। वहां से यह अपने गिरोह के साथ मिलकर राजस्थान के सभी जिलों में नकली नोट सप्लाई करता था। आरोपी के ठिकाने से पुलिस ने नकली नोट बनाने वाला सामान, जिनमें कम्प्यूटर, लोहे की मशीन, नोट का पेपर सहित मशीन को जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 53 हजार 700 हजार रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। इसमें 500, 200 व 100 के नोट शामिल हैं। सरदारपुरा थाने की एसआई रीना कुमारी ने बताया कि नकली नोट मामले में गुरजीत सिंह गुरजीत सिंह (35) पुत्र हंसराज सिंह निवासी कसाबिया वाला मोहल्ला, सोनार, पटियाला को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है।

देश के आठ हाईकोर्ट को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश

SC कॉलेजियम ने केंद्र को भेजा सिफारिश का प्रस्ताव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की कॉलेजियम ने देश के आठ अलग-अलग हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। इनमें दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्यप्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास के हाईकोर्ट शामिल हैं। जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वे अभी दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।

कॉलेजियम ने किया इन न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश

दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जबकि जबकि जस्टिस एमएस रामचंद्र राव जो अभी हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की गई है। उन्हें वर्तमान चीफ जस्टिस बीआर सारंगी के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर ट्रांसफर किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस नितिन जामदार को केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस आर श्रीराम को मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। जस्टिस श्रीराम भी बॉम्बे हाईकोर्ट के ही जज हैं। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ताशी रबस्तान को मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।

मुस्लिम महिलाएं भी पति से हैं गुजारा भत्ता की हकदार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ता मिले की हकदार है। इस वजह से वह गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण-पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। वो इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। हालांकि, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने अलग-अलग फैसला सुनाया लेकिन दोनो की राय समान है। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 दरअसल सेक्युलर लॉ को दरकिनार नहीं कर सकता।

यह था मामला? -अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को।

बदले गए तीन नए कानून कारगर साबित होंगे- एडवोकेट आयुष मल्ल

01 जुलाई 2024 से तीनों नए कानून (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) देशभर में लागू हो चुके हैं। एक ओर जहां केंद्र सरकार इन कानूनों को लेकर यह कह रही है कि ये कानून आजादी के बाद लोगों को न्याय मिलने में मील का पत्थर साबित होंगे तो दूसरी तरफ इन नए कानूनों के विरोध में कुछेक लोगों का कहना है कि ये कानून जल्दबाजी में लाए गये हैं और इनमें व्यापक सुधारों की जरूरत है। कई जगह मात्र तो सिर्फ इनके हिंदी नामों को लेकर ही विरोध हो रहा है।

इन नए कानूनों पर राजस्थान हाईकोर्ट में डिप्टी गवर्मेंट काउंसिल एडवोकेट आयुष मल्ल से बातचीत के अंश-

तीनों नए कानून 01 जुलाई से देशभर में लागू हो गये हैं। सरकार का दावा है कि नए कानून पीड़ितों को न्याय के लिए मिसाल बनेंगे। आपका क्या मानना है?

आजादी के 76 साल बाद भारत के संवैदानिक पदों पर आसीन लोगों ने भारत के निवासियों के लिए भारत का कानून बनाया है। 76 साल के बाद जो तीन ये कानून आये हैं जिससे की हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म हुआ है इसकी तीन प्रमुख बाते हैं सबसे पहली बात है उत्तरदायित्व या जवाबदेही दूसरी बात है पारदर्शिता और तीसरी बात है सुधारात्मक न्याय प्रणाली। उत्तरदायित्व या कहें जवाबदेही का यह मतलब है कि आज हमारे भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है वह और ज्यादा जवाबदेह होगी।

अगर हम सिस्टम या कहें कि कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो कुछ यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी केस शुरू होता है अपराध दर्ज होने (Lodging of Crime) से। अपराध दर्ज होने के बाद जाँच शुरू होती है और फिर उस जाँच से ही फाइनल रिपोर्ट बनती है। उसी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में ट्रायल होती है और ट्रायल पर ही निर्णय आता है।

हम कह सकते हैं कि अब हर स्टेज पर जवाबदेही तय कर दी गई है। यह जवाबदेही अपराध की जाँच Investigation of Crime के दौरान भी है। अब आप जीरों एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड इसमें यूज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर भी आप दर्ज करवा सकते हैं। आप कहीं पर भी घटित अपराध की रिपोर्ट कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस ऑफिसर्स की जवाबदेही पहले से ज्यादा कर दी गई है। जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो इसमें डिजिटल माध्यम को काफी यूज किया गया है। पुलिस जाँच के दौरान घटनास्थल की वीड़ियोग्राफी होगी। जब कोर्ट में यह वीड़ियोग्राफी आयेगी तो सब कुछ साफ रहेगा और कोई भी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकेगा। यदि पुलिस किसी अपराधी को बचाने की कोशिश करेगी तो वह भी पता चल सकेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कोई भी अपने उत्तरदायित्व या कहें जवाबदेही से बच नहीं सकेगा। दूसरी बड़ी बात है पारदर्शिता की। जब घटनास्थल की सारी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं। डिजिटल माध्यम से आज सबकी ऑनलाइन वेबसाइट बन चुकी हैं। ऑनलाइन सबके एप्स बन चुके हैं। क्राइम का क्या डेटा है, क्या स्टेट्स है वो सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं। अपराध की जितनी भी चीजें हैं चाहे वह एफआईआर हो या चार्जशीट सभी इलेक्ट्रॉनिक मोड़ में उपलब्ध होंगी। जब इस प्रक्रिया का सारा डेटा ऑनलाइन होगा तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम में बहुत ही पारदर्शिता आयेगी। सिंगल क्लिक पर जब चाहें, जहाँ चाहें सारा डेटा उपलब्ध रहेगा। तीसरी बात जो आती है वह है सुधारात्मक न्याय प्रणाली (Reformative Justice System) की। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्यूँकि जिस 76 वर्ष पहले के सिस्टम को हम आज तक चला रहे थे वो बहुत ही panic system था यानि कि उस प्रक्रिया से यह लगता था कि यह सिर्फ दण्ड देने के लिए था मतलब दोषियों को सजा देने के लिए था। जबकि भारत की यह जो पुरातात्विक संस्कृति है, हमारी सनातन पद्धति है वह हमेशा यह कहती है कि एक मौका वापिस देना चाहिए। हमारी संस्कृति रिफॉर्म की बात करती है। यह जो तीन नए कानून हैं वे ठीक इसी तरह के हैं। आज ये जो नए भारत के कानून हैं वो यह बताते हैं कि दोषियों को सिर्फ दण्ड ही नहीं देना है बल्कि दण्ड के साथ उनके अंदर सुधार भी लेकर आना है जिससे कि उन्हें समाज में वापिस पुर्नस्थापित करके समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकें।

यह जो तीन नए कानून हैं वह हमारें समाज में महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। कारण यह है कि जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि अलग-अलग जगहों पर वुमन पेट्रोलिंग यूनिट्स, अलग से महिला पुलिस थानें, जितनें भी यौन अपराधों से संबंधित मामलें हैं चाहे वो रेप का अपराध हो या फिर पोक्सों के मामलें हो उसके लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया गया है। अपराध की आसान रिपोर्टिंग होगी। महिला पुलिस अधिकारी इनका अनुसंधान करेंगी। यह एक ऐसा सिस्टम विकसित किया गया है जिससे कि हमारी नारी शक्ति को भी सहूलियत मिलें। सबसे मुख्य बात यह है कि इन तीनों कानूनों को भारतीय संविधान ने अपना लिया है। पूरे देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों ही मिलकर इस पर काम कर रहें हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इससे सोसायटी के ढ़ांचें में भी बदलाव होगा। अपराधों के अनुपात में भी कमी आयेगी। पुलिस स्टेशन की भी डेफिनेशन बदलेगी। अभी तक यह देखा जा रहा था कि आमजन पुलिस स्टेशन जाने से डरता था। लोग सोचते थे कि पुलिस स्टेशन Reporting of Crime के लिए नहीं हैं। लोग डरते थे वहां जाने से। अब नए कानूनों में ऐसी बात है कि पुलिस को भी मित्रवत व्यवहार रखना है। पुलिस थानें जाने वाले आमजन को अब अच्छे से सुना जायेगा। तमाम पहलुओं पर यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि 76 वर्षों के बाद एक नया कानून, नई प्रणाली और नए सिस्टम के साथ पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हुआ है।

लोग कह रहें हैं कि नए कानूनों ने पुलिस को ज्यादा ताकत दे दी है। इससे पुलिस की मनमर्जी बढ़ेगी। पुलिस रिमांड़ की अवधि को लेकर भी एतराज है।

देखिए, ऐसा है कि रिमांड़ दो तरह की होती है। एक होता है न्यायिक रिमांड़ और दूसरा है पुलिस कस्टड़ी। आरोप लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि इसमें पुलिस कस्टड़ी की निर्धारित समय-सीमा बढ़ा दी गई है तो ऐसे में पुलिस इसमें बर्बरता करेगी। ज्यादा समय आरोपी पुलिस के पास रहेगा तो कुछ भी Confection करा जा सकता है। कुछ भी Treatment करा जा सकता है। लेकिन अब इसे कुछ यूँ समझते हैं कि अभी तक सात दिन का पुलिस रिमांड मिलता था। हर सात दिन बाद पुलिस को वापिस कोर्ट में आकर परमिशन लेनी पड़ती थी। समझ सकते हैं कि पुलिस अनुसंधान और न्यायिक निगरानी दोनों साथ-साथ चलते हैं। सात दिन के अंदर गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों के मामलों में पूछताछ ठीक से नहीं हो पाती थी। फिर अगले 7 दिन बाद जाकर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती थी। इस सब में तो कोर्ट का समय ही खराब हुआ ना। ऐसा बार-बार होता था। अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस अब उचित अनुसंधान कर पायेगी। जब कभी भी कोई अपराध होता है तो उसके कई पहलू होते हैं। कई चीजों पर अनुसंधान करना पड़ता है। मानिए की कोई आतंकवादी है तो उससे 7 दिन में उस अपराध के बारें में क्या पूछताछ हो सकेगी। 7 दिन में तो हत्या के मामलें में भी क्या जाँच हो सकती है। पुलिस को रिकवरी भी करनी है वैपन्स की। पूरा क्राइम सीन भी डेवलप करना है। फोरेंसिक रिपोर्टस भी मंगानी है। बहुत सारी क्रॉस क्यूशन भी करनी होती है तो एक जो उपयुक्त समय और अधिकतम समय है अब वो अनुसंधान ऑथिरिटी को देखना है कि उनको कितना टाइम इसमें लगेगा। यह भी बता देना चाहता हूँ कि देश के कानूनविद् जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं और जो आपराधिक न्यायशास्त्र के विशेषज्ञ हैं उनकी कमेटी ने बैठकर देश के गृह मत्रालय, सेवानिवृत्त न्यायाधीश आदि लोगों ने मिलकर इन कानूनों को बनाया है। इसमें कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि इन नए कानूनों से पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक दोस्ताना माहौल बनेगा और काफी आसान तरीका हो जायेगा जिससे सभी को सहूलियत होगी। कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं कि कानून जल्दबाजी में लागू किये गये हैं। उनकी राय को माना नहीं गया है। उनका कहना यह भी है कि पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में धरातल पर काफी दिक्कतें आयेगी। देखिए, तीनों नए कानूनों को लागू करने में जल्दबाजी कहना ठीक नहीं है। सरकार द्वारा अभी से नहीं बल्कि पिछले सालभर से इन तीनों नए कानूनों को लागू करने के लिए सेमिनार आयोजित किये जा रहें हैं। डिबेट्स हो रही है। डिस्कर्सन हो रहें हैं। स्टड़ी सर्किल्स हो रही हैं। ऑनलाइन मीड़ियम पर भी हो रही हैं। सरकार ने खुद इसके लिए वर्चुअल ऐप बना दी। ऐप में सारी जानकारी हैं। सोशल मीड़िया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सअप, ट्यूटर के माध्यम से काफी प्रचार-प्रसार हो रहा है। हमारी विभिन्न बार एसोसिएशन हैं। बार काउंसिल हैं। सभी सेमीनार कर रही हैं। डिस्कर्सन कर रही हैं। एडवोकेट्स खुद भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सब नए बुक्स, बेयर ऐक्टस खरीद रहे हैं और इस पर काफी रिसर्च चल रही हैं। आज सोशल मीड़िया, ऑनलाइन मीड़ियम के माध्यम से हर घर में और साथ ही मीड़िया का भी इसके प्रचार-प्रसार में बड़ा योगदान है। यह केवल एडवोकेट या पुलिस या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब यदि पूरा सिस्टम चेंज हुआ है तो सिस्टम का पार्ट पूरी सोसायटी है। हमारी सभी की साझा जिम्मेदारियाँ हैं। सब मिलकर इसमें चेंज ला रहे हैं। सभी एडवोकेट्स ने इसके बारें में स्टड़ी कर ली है। जैसे-जैसे कानून व्यवहारिकता में आयेगा वैसे-वैसे इसमें नई चीजें आयेगी वो सभी के सामने होंगी।

दक्षिण के राज्य नए कानूनों के सिर्फ हिंदी नामों की वजह से इनका विरोध कर रहें हैं। यह कहां तक जायज है?

हमारा सौभाग्य है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। कोई भी विरोध एक सीमा और जगह तक सही बात है। यदि बात भाषा की है तो ये सारे कानून देशीय सभी भाषाओं में उपलब्ध है। अब यदि इनका नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं और यदि इस भारतीय नाम से ही कुछेक लोगों को परेशानी है तो यह कैसे जायज हो सकता है। यह हमारा भारत सनातन संस्कृति, सनातन पद्धति, सनातन धर्म पर ही खड़ा है। पूरे विश्व की नजर है हमारे भारत पर। आज हमें गर्व होना चाहिए कि हमनें जो नए कानून अपनाए हैं उनका नाम ही भारत पर है। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकेगी कि हमारी भारतीयता पूरे विश्वभर में झलक रही है। जो लोग विरोध कर रहें हैं वो मैरिट पर करें तो अच्छा हो लेकिन सिर्फ नाम पर विरोध करना बिल्कुल अनुचित है। विरोध करने वाले इनके प्रावधानों पर विरोध करें। इन पर तर्क करें। यह भी बता दूँ कि इंटरनल कमेटीज होती है पार्लियामेंट की। मिनिस्ट्री ऑफ होम की। सबने मिल-बैठकर सलाह-मशविरा किया है। यह बिल भारतीय संसद यानि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हुआ है। वहां बैठे लोग पूरे देश से लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आये हुए हैं और वे देश के हर हिस्से के लोगों के प्रतिनिधि हैं। ऐसा कोई विरोध नहीं है। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंड़िया जो वकीलों की सर्वोच्च संस्था भी है उसने भी इन तीनों नए कानूनों का सपोर्ट एवं स्वागत किया है।

जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह होंगे मणिपुर से प्रथम सुप्रीम कोर्ट जज

कॉलेजियम ने की दो जजों की पदोन्नति की सिफारिश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति दिए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह और आर महादेवन के नामों की सिफारिश की है। नियुक्ति के बाद जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले मणिपुर राज्य के पहले न्यायाधीश होंगे। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से उत्तर-पूर्व को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

वर्तमान में 2 जजों की जगह रिक्त-जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह वर्तमान में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस महादेवन मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम के अन्य सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवई, सूर्यकांत और हृषिकेश राय हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सहित 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, वर्तमान में 32 न्यायाधीश हैं।

नीट मामले में गड़बड़ी

18 जुलाई को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट नीट मामला

नई दिल्ली(एजेंसी)। नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि, बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और एनटीए के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। सुनवाई के लिए 11 जुलाई को कोर्ट में नीट का केस 40 से 45 मामले पर लिस्ट किया गया था। केस 33 की सुनवाई के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कल सबसे पहले नीट पर सुनवाई होगी।

एडवोकेट माही यादव, जिनकी PIL ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों में खोला एडमिशन का रास्ता

आज का जो बहरोड़-कोटपूतली जिला है उसका कोटपूतली उस समय जयपुर जिले में ही हुआ करता था। इसी कोटपूतली का एक गांव है भैंसलाना। ये वही भैंसलाना गांव है जिसके काले संगमरमर की पहचान पूरे देशभर में है। मगर आज के समय में गांव की पहचान फिर सुर्खियों में है। जी हां, राष्ट्रीय फलक पर इस चर्चा का कारण है गांव की बेटी एडवोकेट माही यादव जो अपनी काबिलियत के दम पर वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता बनी हैं। एडवोकेट माही यादव अपनी साफगोई के लिए जानी जाती हैं और इसी अंदाज में सरकार का पक्ष रखती नजर आती हैं। अनुशासन के प्रति बेहद ही सख्त मिजाज रखने वाली माही के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू उनका सरल, सौम्य एवं सुलभ होना भी है। आज **''तोड़ों बेड़ियाँ, कम नहीं बेटियाँ''** की खास सीरीज़ में हम जानेंगे कि एडवोकेट माही यादव पर क्यूँ पूरे समाज को नाज होना लाजिमी है।

तारीख़ 07 जुलाई वर्ष 1982 का दिन. गांव के किसान बी. आर. यादव के यहां एक बिटियां जन्म लेती है. नाम रखा जाता है माही. किसान पिता अपनी बेटी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखते हैं या कहें की पालन-पोषण में बेटा-बेटी का भेद कभी नहीं रखा। बेटों के साथ बिटियां को भी स्कूल में दाखिला दिलवाया जाता है। बेटी माही जब अच्छे नंबरों से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो घोड़ी पर बैठाकर शोभायात्रा निकाली जाती है। उसकी हौंसला अफ़जाई के इस अंदाज से समाज को बेटियों के प्रति धारणा बदलने के लिए खास संदेश भी दिया गया। उस वक्त तो शायद ही किसी को यह भान होगा कि यह बेटी आगे चलकर पूरे गांव का ही नाम रोशन करेगी। अपनी शुरुआती शिक्षा गांव से पूरी करने के बाद माही आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर आती है। माही राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलएलबी पास आउट है। कॉलेज के दिनों में माही छात्र हितों के कार्यों में काफी मुखर रही है।

● माही हैं कॉर्पोरेट लॉयर, जस्टिस समीर जैन के चैम्बर से शुरू की थी प्रैक्टिस

एडवोकेट माही यादव राजस्थान हाईकोर्ट की जानी-मानी कॉर्पोरेट लॉयर हैं। माही ने अपनी वकालत की शुरुआत दिग्गज कॉर्पोरेट एडवोकेट समीर जैन के चैम्बर से की थी। बता दें कि वर्तमान में समीर जैन राजस्थान हाईकोर्ट में सीनियर जज हैं। अनुशासन और साफगोई की बात पर माही कहती हैं कि परिवार के बाद मैंने यह सब अपने गुरु समीर जैन साहब से ही सीखा है।

● माही की जनहित याचिका और लड़कियों को मिलने लगा सैनिक स्कूलों में दाखिला

माही जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तब एक रोज अखबार में ऐसा ऐड देखती हैं जो लैंगिक भेदभाव को दर्शाता था। विज्ञापन सैनिक स्कूल में एडमिशन को लेकर था लेकिन वहां जो एक लाइन लिखी थी उसने माही को मानसिक रूप से झकझोर दिया। वह लाइन थी-ओनली फोर बॉयज। माही कहती हैं कि मेरे परिवार से कई पीढ़ियों के लोग भारतीय सेना में रहकर देश सेवा करते आये हैं और मैं उन सभी से सैनिक स्कूल और नेशनल मिलिट्री स्कूल में लड़कियों के एडमिशन नहीं होने की टीस के साथ ही इसकी संभावनाओं के बारे में बात करती रहती थी। कुछ सालों बाद एक सुबह फिर माही की नजर में ऐसा ही विज्ञापन आ जाता है। इस बार माही ठान लेती है कि अब वह चुपचाप नहीं बैठने वाली है। क्यूँकि अब माही वकील बन चुकी थी। अब माही पर महिला अधिकारों की जानकारी के साथ लैंगिक भेदभाव को खत्म करवाने का जज्बा सवार हो चुका था। वर्ष 2016 में एडवोकेट माही ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला दिये जाने एवं इस तरह के लैंगिक भेदभाव को खत्म किये जाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिला की। कोर्ट ने इस पीआईएल पर केंद्र सरकार को आदेश देकर पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। माही की यह कानूनी लड़ाई रंग लाई और इस तरह सैनिक स्कूलों में लड़कियों के एडमिशन की राह खुली।

● लोगों के चेहरों की खुशी देती है सच्चा सुकून

एडवोकेट माही यादव कहती हैं कि लोगों के चेहरों की खुशियां ही उन्हें सच्चा सुकून देती हैं। यह सब संस्कार पारिवारिक विरासत में मिलना बताती है। माही कहती हैं कि उन्हें पब्लिक इश्यूज पर काम करना पसंद है। इसके लिए इन्हें दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। माही लोगों के खिले चेहरों को ही अपनी सबसे बड़ी फीस मानती हैं और नेकदिली को ही अपना फर्ज।

● निराली है देशप्रेम की भावना

माही की देशप्रेम की भावना भी अजब है। माही कहती हैं कि यूँ तो मुझे सिर्फ खूब पढ़ने का ही शौक है लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ है तो वह है राष्ट्रगान गाना-सुनना। माही बताती है कि उस समय मैं सिर्फ 5-6 कक्षा में हुआ करती थी जब हमारे घर में पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया। परिवार के सभी लोग एक साथ समाचार देखते और रात 10.30 बजे आने वाला सीरियल परमवीर चक्र। परिवार के लोग भारतीय सेना में रहकर देशसेवा कर रहे थे ऐसे में देशप्रेम की भावना तो संस्कारों में ही मिली है लेकिन परमवीर चक्र सीरियल से राष्ट्रगान ने बालमन पर ऐसी जगह बना ली जो कि हमेशा के लिए अमिट रहेगी। माही सिर्फ इसलिए क्रिकेट मैच या फिल्में देखती हैं कि दोनों के शुरू होने से पहले दर्शकों द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान होता है तो उन्हें एक ही समय में करोड़ों लोगों द्वारा देखा-सुना जाता है और देशप्रेम की लौ एक साथ लोगों के दिलों में धड़कती है।

● जानवरों के प्रति दयालुता ऐसी की गाड़ी में लेकर घूमती हैं उनके लिए खाना-पानी

एडवोकेट माही यादव की जानवरों के लिए दयालुता कुछ ऐसी है कि उनके लिए खाना-पानी गाड़ी में लेकर ही घूमती हैं। छोटू (वह दूधमुहां पिल्ला जो बचपन में ही अपनी मां से बिछड़ गया था या उसे हमेशा के लिए खो दिया था) और सुनहरी इनके परिवार के अभिन्न अंग बन चुके हैं। जिस आवासीय सोसायटी में माही रहती हैं वहां नीचे ऐसे ही बेजुबान भूखे-प्यासे जानवरों के लिए खाना-पानी की व्यवस्था करके रखती हैं। इनके लिए माही कहती हैं कि लोग कहते है कि जानवर बोलते नहीं हैं लेकिन ये बोलते भी हैं और समझते भी हैं बस हमें इन्हें समझना आना चाहिए।

● राष्ट्रीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं में कानूनी जागरूकता वाले आलेख होते हैं प्रकाशित

एडवोकेट माही यादव लोगों को अपने अधिकारों को जानने के लिए कहती हैं। इसके लिए इनके द्वारा बहुत कुछ लिखा भी जाता है। कानूनी जानकारी देने वाले इनके आलेख देश के राष्ट्रीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं जो कि आमजन के साथ ही कानूनी पढ़ाई वाले छात्रों के लिए बहुत ही मददगार होते हैं।

हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय दिए एफएसएल डायरेक्टर को उपस्थिति के निर्देश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में 10 जुलाई को एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय जस्टिस गणेश मीणा ने एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा को 16 जुलाई की सुनवाई में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार अलवर रामगढ़ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 307, 384 द्वश्र एवं अन्य धारा में दर्ज हुई थी जिसमें 2 अभियुक्त तेजेंद्र एवं अन्य की बेल हाई कोर्ट में लंबित थी एवं बहस हो रही थी। अभियुक्त के अधिवक्ता ने जब कहा कि इस प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट आ चूकी है तब परिवादी कि और से जमानत का विरोध कर रहे अधिवक्ता पवन शर्मा ने न्यायालय का ध्यान इस और आकर्षित किया कि क्या सभी प्रकरण में एफएसएल से रिपोर्ट इतनी जल्दी आ जाती है जबकि कोर्ट ने भी इस प्रकरण में कोई आदेश नहीं दिए। अधिवक्ता पवन शर्मा ने जमानत का पूरजोर विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकरण में 30 दिन में रिपोर्ट आ जाना कोई सामान्य बात नहीं हो सकती है जबकि अन्य प्रकरणों में मंगाने पर भी रिपोर्ट नहीं आती है और कई बार तो ट्रायल समाप्त होने पर ही रिपोर्ट आती है। जिस पर जस्टिस गणेश मीना ने सहमति जताते हुए एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा को 16 जुलाई की अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गये। तब तक के लिए बेल की सुनवाई टाल दी गयी है।

दी बार एसोसियेशन जयपुर की ओर से नये आपराधिक कानूनों पर कार्यशाला आयोजित

जयपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर महानगर, जयपुर बनीपार्क के प्रांगण में दी बार एसोसियेशन जयपुर के सभागार में 08 जुलाई को दी बार एसोसियेशन जयपुर की ओर से नये आपराधिक कानूनों पर कार्यशाला आयोजित की गयी। सेमिनार में डॉ अरूणा चौधरी एसोसियेट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भारतीय न्याय संहिता पर एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता निक्षित दीक्षित ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर अधिवक्तागण को विस्तार से जानकारी साझा की। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने नये कानूनों को समझकर काफी विचार-विमर्श किया। आयोजित कार्यक्रम के अंत में बार एसोसियेशन के अध्यक्ष पवन शर्मा एवं महासचिव राजकुमार शर्मा ने अतिथिगण का स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार प्रकट किया गया।

हाईकोर्ट ने की पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत रद्द, बिजली विभाग के JEN से की थी जानलेवा मारपीट, 30 दिन के अंदर करना होगा सरेंडर

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर के बाड़ी से पूर्व कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को मिली जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने मलिंगा को 30 दिनों में सरेंडर करने का आदेश दिया है। मामला धौलपुर जिलें में बिजली विभाग के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत रद्द करवानें की याचिका पर पीड़ित बिजली विभाग के अधिकारी हर्षाधिपति की और से वकील एके जैन और मालती ने पैरवी की है। हाईकोर्ट अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि 2 साल बाद आज कोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा को 30 दिन के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने याचिका के दस्तावेजों के निरीक्षण पर पाया कि गिर्राज सिंह मलिंगा ने झूठ बोलकर जमानत ली है। उन्होंने बेल मिलने के बाद इसका गलत लाभ लिया और जमानत के बाद जूलुस निकाल कर कोर्ट के आदेश का मजाक बनाया।

एसएमएस में भर्ती पीड़ित इंजीनियर हर्षाधिपति और पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा

सरकारें कानून से ऊपर नही - अधिवक्ता ए के जैन

पीड़ित इंजीनियर हर्षाधिपति के अधिवक्ता ए के जैन का कहना है कि गिर्राज सिंह मलिंगा की मदद तत्कालीन सरकार के साथ-साथ वर्तमान सरकार ने भी की लेकिन दो साल के बाद पीड़ित सहायक अभियंता को न्याय मिला है। बता दें कि पीड़ित इंजीनियर हर्षाधिपति पिछले दो साल से एसएमएस अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिवक्ता ए के जैन ने इस फैसले पर कहा है कि यह न्याय तो है ही लेकिन उन राजनेताओं के लिए अदालती संदेश भी है कि राजनेता यह समझ लें कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा

पीड़ित इंजीनियर हर्षाधिपति

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे मलिंगा

गिर्राज सिंह मलिंगा पहले कांग्रेस में थे और बाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 27 मार्च 2022 को विधायक रहते ही पीड़ित इंजीनियर हर्षाधिपति से उनके दफ्तर में जाकर इन्होंने अपने समर्थकों के साथ जानलेवा मारपीट की थी। पहले तो गिर्राज मलिंगा का अपने विधायकी वाले रूतबे के कारण कुछ नहीं हुआ लेकिन बाद में जब पीड़ित इंजीनियर को न्याय के लिए जनता सड़कों पर उतरी तब जाकर उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। बाद में उन्होंने हाईकोरेट से जमानत ले ली थी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मलिंगा कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।

याचिकाकर्ता के वकील

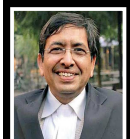
एड़वोकेट ए के जैन

एड़वोकेट मालती

बाजार Market

बिजनेस की खबर - एक नजर

एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए क्यों है ई-केवाईसी जरूरी, कब तक चलेगी प्रक्रिया

नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां फर्जी उपभोक्ताओं को हटाने के लिए रसोई गैस ग्राहकों का आधार के जरिये ई-केवाईसी सत्यापन कर रही हैं। आधार की मदद से ई-केवाईसी (ऑनलाइन ग्राहक सत्यापन) की प्रक्रिया उन फर्जी ग्राहकों को अलग करने के लिए की जाती है, जिनके नाम पर बुक कराई गई रसोई गैस का इस्तेमाल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है।परिवारों को 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 803 रुपये की दर से खरीदना पड़ता है, जबकि होटल एवं रेस्तरां जैसे कॉमर्शियल जगहों को 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर 1,646 रुपये में मिलता है। वहीं, लखनऊ में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 840.50 रुपये तो कॉमर्शियल सिलेंडर 1758.50 रुपये में मिल रहा है। पंजाब के अमृतसर में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज गुरुवार 11 जुलाई को 1743.5 रुपये है तो घरेलू की 844 रुपये।पुरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा। उनका यह पोस्ट केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन के जवाब में आया है, जिन्होंने इस निर्णय के चलते आम आदमी को अप्रत्याशित मुश्किल पेश आने की बात कही थी। सतीशन ने पुरी को लिखे एक पत्र में यह मामला उठाया था।ईकेवाईसी की प्रक्रिया पिछले आठ महीने से चल रही है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने ईकेवाईसी की अंतिम तिथि को लेकर स्पष्ट कर दिया कि ईकेवाईसी कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। एलपीजी डिलीवरी कर्मी ग्राहक को एलपीजी सिलेंडर देते समय क्रेडेंशियल सत्यापित करते हैं। डिलीवरी ब्वाय अपने मोबाइल फोन पर एक ऐप के जरिए से ग्राहक के आधार क्रेडेंशियल कैप्चर करते हैं। ग्राहक को एक ओटीपी मिलता है, जिससे ई-केवाइसी पूरी हो जाती है। इसके अलावा ग्राहक अपनी सुविधानुसार वितरक शोरूम से भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं, एलपीजी उपभोक्ता आईओसी, एचपीसीएल जैसी कंपनियों के ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने आप ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं।

टीसीएस के नतीजों के बाद खटाखट बढ़ने लगे आईटी कंपनियों के शेयर

नई दिल्ली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के गुरुवार को आए पहली तिमाही के नतीजों से आईटी कंपनियों के शेयरों को पंख लग गए हैं। शेयरों के भाव खटाखट बढ़ रहे हैं।अब निफ्टी आईटी इंडेक्स में 4.20 पर्सेंट का बंपर उछाल है। इसमें शामिल टीसीएस में 6.02 फीसद की तेजी है। एम्फेसिस में 5.83, कोफोर्ज में 6.48, एलटीआईमाइंडट्री में 3.28, विप्रो में 4.47, पर्सिस्टेंट में 4.75, एलटीटीएस में 3.26 पर्सेंट की तेजी है। एचसीएल टेक में 2.79, टेक महिंद्रा में 2.99 और इन्फोसिस में 3.09 फीसद की उछाल है। टीसीएस में 4.13 फीसद की तेजी है। एम्फेसिस में 5.46, कोफोर्ज में 5.18, एलटीआईमाइंडट्री में 4.13, विप्रो में 4.13, पर्सिस्टेंट में 3.75, एलटीटीएस में 3.28 पर्सेंट की तेजी है। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में भी अच्छी-खासी बढ़त है।आज निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2.20 की तेजी है। शुरुआती कारोबार में इस इंडेक्स में शामिल सभी 10 स्टॉक्स हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे। विप्रो, एम्फेसिस, एलटीआई माइंडट्री से लेकर टेक महिंद्रा तक में 3.76 पर्सेंट की उछाल थी।टीसीएस के शेयर 2.91 पर्सेंट ऊपर 4037.50 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। आज यह स्टॉक एनएसई में 3980 रुपये पर खुलकर दिन के हाई 4044.90 रुपये पर पहुंच गया। कुल 31,69,066 शेयर में ट्रेडिंग हो रही है। जबकि, एम्फेसिस के शेयरों में 3.76 पर्सेंट की उछाल है। आज यह स्टॉक 2709.50 रुपये पर पहुंचने के बाद सुबह सवा दस बजे के करीब 2656.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

एलटीआईमाइंडट्री के शेयर भी 123.90 रुपये उछले- विप्रो की बात करें तो आज इसमें 3.32 पर्सेंट की तेजी है और यह 545 रुपये पर खुलने के बाद 551.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एलटीआईमाइंडट्री के शेयर भी 123.90 रुपये उछल कर 5531.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कोफोर्ज के शेयर में 121.50 रुपये की बढ़त है और यह 5685 रुपये पर पहुंच गया है।

मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से खासी उम्मीदें

हर वर्ग को फायदा देने की चुनौती

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से खासी उम्मीदें हैं। निम्न और मध्यवर्ग को सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिये विशेष लाभ दे सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी आयकर छूट सीमा बढ़ाए जाने और स्लैब में परिवर्तन किए जाने की चर्चाएं हैं। बदले हुए समीकरणों के बीच सरकार के लिए यह बजट सहयोगी दलों के अपने राज्यों की मांगों के चलते चुनौतियों से भरा भी है।केंद्र की मोदी सरकार पर हर वर्ग की झोली में कुछ न कुछ डालने का दबाव है। चूंकि चार राज्यों के चुनाव सामने हैं, ऐसे में इन राज्यों के लोगों की भी उम्मीदें टिकी हैं। राजनीतिक रूप से सरकार को मतदाताओं को साधने की भी कवायद करनी पड़ रही है। सरकार की कोशिश होगी कि वह अपने बिखरे जनाधार को समेटने और सहयोगी दलों के साथ तालमेल को बेहतर बनाए। इसलिए 23 जुलाई को जब केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट प्रस्तुत करेंगी तो उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बजट से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उनसे जुड़े संगठन प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री बैठकें कर चुकी हैं। अब

बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

ये बड़ी घोषणाएं संभव- आयकर स्लैब- अभी तक की बैठकों के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आयकर छूट सीमा में बदलाव करेगी। इससे मध्यवर्ग और नौकरीपेशा लोगों को खासा लाभ होगा। इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुरानी और नई व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं।

किसान सम्मान निधि- किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि छह हजार रुपये से बढ़ाकर 10-12 हजार रुपये कर सकती है। कृषि उत्पादों पर कर की दरों को कम करने का फैसला भी हो सकता है।

मजदूरों और कर्मचारियों को ज्यादा लाभ- मनरेगा मजदूरी को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। साथ ही, मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी तक सरकारी कर्मचारी नाखुश हैं।

रोजगार- बदले समीकरणों के बीच सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट बढ़ाने की पूरी संभावना है। अग्निवीर जैसी योजना में भी सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान किया जा सकता है।

ई-मार्केट पोर्टल पर पहली तिमाही में खरीद 1.24 लाख करोड़ रुपये के पार

नयी दिल्ली। सरकार के ई-खरीद पोर्टल जीईएम के जरिये 2024-25 की पहली तिमाही में वस्तुओं व सेवाओं की खरीद 1.24 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। खरीद की यही गति बने रहने से जीईएम चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन जाएगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह बात की। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) मंच की शुरुआत नौ अगस्त, 2016 को की गई थी। जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रशांत कुमार सिंह ने यहां पत्रकारों से कहा, '' जीईएम ने पहली (अप्रैल-जून) तिमाही के अंत में 1,24,761 लाख करोड़ रुपये का सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया, जो तिमाही वार पिछले वर्ष के 52,670 करोड़ रुपये की तुलना में 136 प्रतिशत अधिक है।''

एलन मस्क पर डॉलर की बारिश थमी, एक ही दिन में 15.9 अरब डॉलर की लगी सेंध

नई दिल्ली। इस महीने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ऊपर होने वाली डॉलर की बारिश गुरुवार को थम गई। मस्क के नेटवर्थ में एक ही दिन में 15.9 अरब डॉलर की सेंध लग गई। हालांकि, मस्क अभी भी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर हैं। दूसरे पर जेफ बेजोस और तीसरे पर बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं। **टेक कंपनियों से जुड़े अरबपतियों को बड़ा झटका-**अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क टॉप लूजर रहे। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में गुरुवार के टॉप-8 लूजर टेक कंपनियों से हैं। एलन मस्क ने 15.9 अरब डॉलर गंवाए, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 7.57 अरब डालर का झटका लगा तो एनवीडिया के मालिक जेनसेन हुआंग को 6.49 अरब डॉलर का। अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस को 4.70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ तो अल्फाबेट के को-फाउंडर लैरी पेज को 4.10 अरब डॉलर की चोट पहुंची। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के ही दूसरे को-फाउंडर सर्गी ब्रिन को भी 3.81 अरब डॉलर का फटका पड़ा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर को 3.64 अरब डॉलर और Dell Technologies के चीफ एग्जीक्यूटिव माइकल डेल को 2.42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

भीषण गर्मी के बाद तेज बारिश से सब्जियों के दामों में उछाल बढ़ा सकती है महंगाई दर

खुदरा मुद्रास्फीति का आधिकारिक डेटा 12 जुलाई को जारी होने वाला है। 18 अर्थशास्त्रियों के औसत अनुमान के अनुसार, यह छह महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति में पहली वृद्धि होगी।

नई दिल्ली। सब्जियों की ऊंची कीमतों के कारण जून की खुदरा मुद्रास्फीति 4.9% हो सकती है, जो मई में 4.75% थी। मिंट द्वारा सर्वेक्षण में शामिल 18 अर्थशास्त्रियों के औसत अनुमान के अनुसार, यह छह महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति में पहली वृद्धि होगी, लेकिन जून 2023 से अनुकूल आधार ने वृद्धि की मात्रा को सीमित करने में मदद की है। सर्वेक्षण में अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.56% से 5.14% के बीच जताया गया। खुदरा मुद्रास्फीति का आधिकारिक डेटा 12 जुलाई को जारी है।

खाद्य मुद्रास्फीति एक बड़ा सिरदर्द- भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर औसतन 4.5त्न रहेगी। हालांकि, लगातार बढ़ी हुई खाद्य मुद्रास्फीति और उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता केंद्रीय बैंक के लिए एक बड़ा सिरदर्द रही है। सब्जियों के अलावा, दाल और दूध की कीमतों ने जून में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ाया है।डॉयचे बैंक ने पिछले सप्ताह एक टिप्पणी में कहा था कि जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पांच प्रतिशत के करीब पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि विशेष रूप से सब्जियों के कारण खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण होगी।

मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य पदार्थ की हिस्सेदारी 40%-खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति की गणना लगभग 40% हिस्सा हैं। खाद्य मुद्रास्फीति ने नवंबर 2023 से लगातार 8% से अधिक वृद्धि दर्ज की है। तब से सब्जियों की कीमतें दोहरे अंकों में बढ़ रही हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इस महीने से टेलीकॉम कंपनियों की 25 फीसदी तक टैरिफ बढ़ोतरी से आने वाले महीनों में महंगाई पर कम से कम 0.2 फीसदी तक दबाव बढ़ने की संभावना है।

ब्याज दर में कटौती का माहौल बन रहा-पिछले महीने, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा था। हालांकि पैनल के छह सदस्यों में से दो ने दर में कटौती के लिए मतदान किया। ,

बार्कलेज ने पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट में कहा, निकट अवधि में, आरबीआई की उम्मीद के मुताबिक जुलाई-सितंबर में प्रमुख मुद्रास्फीति में भारी गिरावट आ सकती है।

हर समय चलता रहता है दिमाग में कोई ख्याल, तो यहां हैं आपके लिए कुछ मेडिटेशन टिप्स

मेडिटेशन एक सीखा हुआ कौशल है जो अभ्यास और धैर्य के साथ ही बेहतर होता जाता है। जब आप एक नियमित शेड्यूल बनाए रखते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप समझ जाता है कि यह समय आराम करने का समय है।क्या आपका दिमाग कभी बंद नहीं होता? क्या आप आराम करने की कोशिश करते समय लगातार चीजों के बारे में सोचते रहते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत ज़्यादा सोचना आम बात है और बहुत लोगों के साथ ये समस्या लगातार बनी रहती है। इसके कारण कई समस्याएं होते है। ऐसे में आप मेडिशन की कोशिश करने के समय भी अपने दिमाग को बंद नहीं कर पाते है।जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपका दिमाग लगातार चलता रहता है, बार-बार एक ही स्थिति के बारे में सोचता रहता है, अलग-अलग चीजें जो आप कर सकते थे या कह सकते थे, या यहां तक कि ऐसी चीजें जो भविष्य में हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाला दिमाग आराम के लिए भी नहीं रूकता है। ऐसा करने वाले लोग वर्तमान में नहीं जी पाते है। जिसके कारण बहुत समस्या हो सकती है। दिमाग को शांत करने का एक तरीका है वो है मेडिटेशन अब ज्यादा सोचने वालों के लिए ये एक चुनौती है तो चलिए जानते है कि अगर आप भी ओवरथींक करते है तो कैसे मेडिटेशन में अपने दिमाग को स्विच ऑफ करें।

ओवरथिंकर के लिए मेडिटेशन के कुछ टिप्स

*1 **एक नियमित शेड्यूल बनाए रखें**-मेडिटेशन एक सीखा हुआ कौशल है जो अभ्यास और धैर्य के साथ ही बेहतर होता जाता है। जब आप एक नियमित शेड्यूल बनाए रखते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप समझ जाता है कि यह समय आराम करने का समय है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने मेडिटेशन अभ्यास के साथ सख्त हो जाएं। मेडिटेशन का मतलब नियमों का पालन करना नहीं है, इसका मतलब है वह करना जो अभ्यास करने वाले को अच्छा और सही लगता है।*

*2 **मेडिटेशन के लिए एक स्थान रखें**-खासकर अधिक सोचने वाले व्यक्ति के लिए, कपड़े धोने, अव्यवस्था या बच्चों से घिरे हुए जगह पर मेडिटेशन का अभ्यास करना सही नहीं है। अधिक सोचने के लिए ध्यान का अभ्यास करने के लिए, आपको मेडिटेशन के लिए एक शांत स्थान की आवश्यकता होती है।*

सुबह करें ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दूर होगी मॉर्निंग लेजीनेस और स्टिफनेस

सुबह उठने के साथ बेड पर अपनी बॉडी को कुछ देर स्ट्रेच करें, ऐसा करने से आपको स्वयं अपनी दिनचर्या में बदलाव नजर आएगा। ज्यादातर लोगों को सुबह उठने के बाद बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता उन्हें बेहद आलस महसूस होती है। इतना ही नहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मॉर्निंग स्टीफनेस की भी शिकायत रहती है। यानी कि सुबह उठने के साथ उनकी हाथ, पैर एवं मांसपेशियां अकड़ी हुई महसूस होती हैं। साथ ही साथ उन्हें दर्द की शिकायत भी रहती है। ऐसे में कुछ सामान्य बॉडी स्ट्रेचेज इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। सुबह उठने के साथ बेड पर अपनी बॉडी को कुछ देर स्ट्रेच करें, ऐसा करने से आपको स्वयं अपनी दिनचर्या में बदलाव नजर आएगा।लाइफस्टाइल कोच एवं फिटनेस एक्सपर्ट यश अग्रवाल ने कुछ खास तरह के स्ट्रेच और व्यायाम करने की सलाह दी है, जो आपको सुबह की आलस्य से छुटकारा पाने और पूरे दिन एनर्जेटिक रहने में मदद करेंगे।

पहले जानें स्ट्रेचिंग किस तरह मॉर्निंग स्टीफनेस और लेजीनेस को कम करने में मदद करती है-बॉडी स्ट्रैचिंग शरीर में लचीलापन लाती है, साथ ही साथ मांसपेशियों को भी फ्लैक्सिबल बनती है। जिससे कि बॉडी स्टीफनेस काम होता है। कई बार थकान की वजह से भी सुबह उठने के बाद आलस और मांसपेशियों में अकड़न महसूस होता है, ऐसे में स्ट्रेचिंग करने से मसल्स टेंशन रिलीज होती है और आपकी मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं।साथ ही साथ स्ट्रेचिंग इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है, जिससे कि बॉडी स्टीफनेस भी कम हो जाता है। इतना ही नहीं स्ट्रेचिंग ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और शरीर में सभी ओर पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचता है। ऐसे में मांसपेशियां और हड्डियां सभी एक्टिव और हेल्दी रहती हैं।

यहां जानें कुछ बॉडी स्ट्रेचेज़ के बारे में

1. नेक स्ट्रेच -धीरे-धीरे अपने सिर को एक तरफ से दूसरी ओर झुकाएं, प्रत्येक स्थिति को 10-15 सेकंड तक होल्ड करें।धीरे-धीरे अपनी गर्दन को दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाएं।

2. शोल्डर-अपने कंधों को धीमे और नियंत्रित तरीके से आगे और पीछे की ओर घुमाएं।

3. अपर बैक स्ट्रेच -अपने हाथों को आपस में मिलाएं और उन्हें अपने सामने फैलाएं, अपनी ऊपरी पीठ को थोड़ा सा गोल करें।इसे दो से तीन बार दोहराएं आपको फौरन आराम महसूस होगा।

4. स्पाइन ट्विस्ट -अपने बिस्तर या कुर्सी के किनारे पर पैरों को ज़मीन पर सपाट रखकर बैठें।अपने ऊपरी शरीर को एक तरफ घुमाएं, और 10-15 सेकंड तक होल्ड करें, फिर साइड बदलें।

5. हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच -सबसे पहले खड़ी हो जाएं और एक पैर को आगे की तरफ़ बढ़ाएं, अपनी एड़ी को ज़मीन पर रखें और पंजों को ऐसे रखे जैसे वे ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हो।कूल्हों पर थोड़ा आगे की ओर झुकें जब तक कि आपको अपनी जांघ के पिछले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस न हो।

6. काफ स्ट्रेच-एक पैर को दूसरे के सामने रखकर दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। अपने सामने वाले घुटने को थोड़ा मोड़ें और अपनी पिछली एड़ी को ज़मीन पर दबाएं, ताकि आपकी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो।

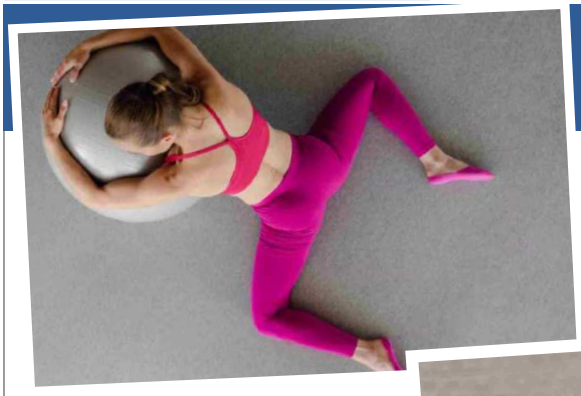

जांघों,कूल्हों और पैल्विक मसल्स को मजबूत बनाता है मंडूकासन, इन स्टेप्स के साथ करें इसका अभ्यास

फ्रॉग पोज़ कूल्हे के जोड़ों के लचीलेपन और मूवमेंट को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यह मुद्रा कूल्हे के जोड़ों, कमर और भीतरी जांघों को फैलाती है, जो इन क्षेत्रों में तनाव और जकड़न को कम करने में मदद कर सकती है।क्या आपने कभी मेंढक की तरह छलांग लगाने की कोशिश की है? वैसे, योग मुद्रा मंडूकासन शायद आपको ऐसी ऊंची छलांगों के लिए बिल्कुल तैयार न करे, लेकिन इसे अभ्यास करने के कई अन्य कारण हैं। चलिए आज आपको बताते है कि आपको फ्रॉग पोज़ क्यों करना चाहिए। मंडूकासन योग परंपरा के पुराने आसनों में से एक है। 17वीं सदी के क्लासिक हठ योग ग्रंथ घेरंडा संहिता में इसे योग के 32 सबसे मूल्यवान आसनों में से एक बताया गया है। इस मुद्रा का एक और आम नाम ÷जंपिंग फ्रॉग पोज़÷ है क्योंकि यह कूदने वाले मेंढक की मुद्रा जैसा दिखता है।आसन का अभ्यास पारंपरिक रूप से बैठकर ध्यान करने की मुद्रा के रूप में तैयार किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंडूकासन उन क्षेत्रों को गतिशील करने में मदद कर सकता है जो हमें आसान मुद्रा (सुखासन) और शायद लोटस मुद्रा (पद्मासन) में भी आराम से बैठने की अनुमति देते हैं। मंडूकासन एडिक्टर्स, कमर क्षेत्र और पेट को टारगेट करता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छी मुद्रा है जो अपनी आंतरिक जांघ का लचीलापन बढ़ाना चाहते हैं।

अपने एक्सरसाइज रूटीन में फ्रॉग पोज़ को शामिल करने के

लाभ

फ्रॉग पोज़ शरीर, मन और आत्मा के लिए कई चिकित्सीय लाभ हैं। इस मुद्रा के कुछ फायदे आज हम आपको बताते है।

1 कूल्हे का लचीलापन बढ़ाता है-फ्रॉग पोज़ कूल्हे के जोड़ों के लचीलेपन और मूवमेंट को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यह मुद्रा कूल्हे के जोड़ों, कमर और भीतरी जांघों को फैलाती है, जो इन क्षेत्रों में तनाव और जकड़न को कम करने में मदद कर सकती है।

2 पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाता है-फ्रॉग पोज़ पेट के अंगों पर हल्का दबाव डालती है, जो स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। इससे आपकी ब्लोटिंग, अपच या गैस क समस्या को दूर करने में भी मगग मिलती है। ये आरन आपके पेट के हिस्से को लचीला बनाने में भी मदद करता है।

3 तनाव से राहत देता है-फ्रॉग पोज़ शरीर में तनाव और स्ट्रेस को दूर करने में मदद कर सकती है। इस मुद्रा को करते समय आपको गहरी सांस लेनी होती है, जो मन को शांत करने और चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। इससस आपका दिमाग शांत होता है।

4 ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है-फ्रॉग पोज़ कूल्हे और पैर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह मुद्रा इन क्षेत्रों में रक्त के प्रवाह को ठीक कर सकती है, जो सूजन को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। अगर आपके कूल्हों या पैरों में दर्द रहता है तो इन आसनों को करें। **5 कोर को मजबूत बनाता है** -फ्रॉग पोज़ पेट और पीठ के निचले हिस्से सहित कोर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। मुद्रा के लिए संतुलन और स्थिरता की आवश्यकता होती है, जो आपके पूरे कोर की शक्ति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।**फ्रॉग पोज को करने का सही तरीका** -अपने शरीर को वॉर्म करने के लिए कुछ मिनटों की हल्की स्ट्रेचिंग या योगा सीक्वेंस से शुरुआत करें। कूल्हों, भीतरी जांघों और पीठ के निचले हिस्से पर ज्यादा ध्यान दें। टेबलटॉप पोजीशन में अपने हाथों और घुटनों के बल आएं। सुनिश्चित करें कि आपकी कलाई आपके कंधों के नीचे और आपके घुटने सीधे आपके कूल्हों के नीचे हों। धीरे-धीरे अपने घुटनों को चौड़ा करें, उन्हें साइड में ले जाएं। अपने टखनों को अपने घुटनों के साथ लाइन में रखें और अपने पैरों को इस तरह मोड़ें कि आपके पैरों के अंदरूनी किनारे फर्श पर दबाव डाल रहे हों।

प्रौद्योगिकी शिक्षा के तहत विश्वविद्यालय युवाओं को नवाचारों से जोड़ते हुए शोध की मौलिक भारतीय दृष्टि से संपन्न करें:राज्यपाल

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को कौशल विकास से जोड़ने के साथ ही मौलिक शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रेरित करने वाली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स) का है, इसका उपयोग मानवता के कल्याण से जुड़े विषयों में हो। उन्होंने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे पृथ्वी पर हो रहे जलवायु परिवर्तन व अन्य विभिन्न प्रकार के संकटों को सुलझाने में अपना योगदान दें। साथ ही नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इस पर भी तकनीकी शिक्षा आधारित हो। इसके लिए गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों व नवीन प्रयोगों के लिए शोध एवं अनुसंधान करें। साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लिथियम बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन, सौर व पवन ऊर्जा, नाभिकीय संवर्धन के निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में नवीन नवाचार हों। उन्होंने विद्यार्थियों का चक्रवात, सुखा, बाढ़, भूस्खलन जैसे संकटों में अभियांत्रिकी के उपयोग से आपदाओं के समुचित प्रबंधन में संवाहक बनने का आव्हान किया। मिश्र ने कहा कि प्रौद्योगिकी शिक्षा का लक्ष्य भारत को विश्व में उत्पादन की दृष्टि से महाशक्ति के रूप में उभारना है। साथ ही, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत मेक इन इण्डिया, स्टेन्ड अप इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया इत्यादि के तहत भारत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नये कीर्तिमान स्थापित करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कार्यरत इन्क्युबेशन एवं स्टार्ट अप प्रकोष्ठ इस दिशा में कार्य करें। यह विश्वविद्यालय देश के चुनिन्दा विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल हैं। यहां पेट्रोलियम में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ होना अच्छी पहल है। इससे पेट्रोलियम रिफाईनरी में भी युवाओं को अवसर मिलेंगे।

संविधान स्तम्भ का किया लोकार्पण -राज्यपाल और कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नए परिसर में स्थित नवनिर्मित संविधान स्तम्भ का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि संविधान हमारी उदात्त जीवन परम्पराओं का संवाहक है। साथ ही, उन्होंने ने युवाओं से आह्वान किया कि भारत के नव-निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए संविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्यों को आचरण में लाकर आगे बढ़ें। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केएल श्रीवास्तव, कुलसचिव ओपी जैन, वित्त नियंत्रक, सिंडीकेट व सीनेट सदस्य, अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक, अधिकारी सहित कर्मचारीण उपस्थित रहे।उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में केन्द्र सरकार की परियोजना के सामरिक दृष्टि के महत्व के तहत 5जी स्पेक्ट्रम प्रयोगशाला प्रारम्भ की गयी है।

न्यूज ब्रीफ

विदेश में उच्च अध्ययन के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना को बंद करने का विचार नहीं : अविनाश गहलोत

जयपुर(नि.सं.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को राज्य विधान सभा में आश्वस्त किया कि विदेश में उच्च अध्ययन के लिए मेधावी विधार्थियों को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार दी जाने वाली छात्रवृत्ति को बंद नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व में यह योजना राजीव गाँधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के नाम से संचालित थी, जिसमें 500 छात्रों को प्रतिवर्ष लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य था। वर्तमान सरकार ने योजना का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर संशोधित कर लाभान्वित किये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी संशोधन किया है।

आवंटन सलाहकार समिति के गठन के बाद उचित मूल्य की नई दुकानें खोली जाएगी : सुमित गोदारा

जयपुर(नि.सं.)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कहा कि आवंटन सलाहकार समिति के गठन के बाद प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार उचित मूल्य की नई दुकानें खोली जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री लक्ष्मण के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विगत एक वर्ष में उचित मूल्य के दुकानदारों के विरूद्ध कुल 1560 शिकायतें प्राप्त हुई। उन्होंने प्राप्त शिकायतों का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। गोदारा ने जानकारी दी कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विगत एक वर्ष में कुल 2 राशन डीलरों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए राशन डीलर श्री नन्दकिशोर मीणा का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ संवेदनशील रहें : अविचल चतुर्वेदी

जयपुर(नि.सं.)। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् श्री अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों (सीडब्ल्यूएसएन) एवं उनके अभिभावकों के साथ मॉडल रिसोर्स रूम का स्टाफ संवेदनशील एवं आत्मीय व्यवहार करते हुए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें।

राजस्थान विधानसभा में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने माना

सफाईकर्मियों की भर्ती में लेन-देन की शिकायतें मिलीं

एक कर्मचारी पैसे लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ा, भर्ती की दे रहा था गारंटी

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान विधानसभा में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने माना कि सफाईकर्मियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर पैसे के लेन-देन की शिकायतें मिलीं। कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया के मुद्दा उठाए जाने पर यूडीएच मंत्री ने कहा कि यह भर्ती जल्द करवाई जाएगी। खर्रा ने कहा- 12 जून 2024 को एक सफाईकर्मी एसीबी के हत्थे चढ़ा, जो गारंटी के साथ भर्ती करवाने के नाम पर आवेदक से 1.75 लाख रुपए ले रहा था। इस प्रकार की शिकायत हमें बहुत मिली थीं, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति जाल में फंसा, बाकी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने गहलोत राज में 2021 में जोधपुर में खोले गए एमबीएम यूनिवर्सिटी को बंद करने के मांग उठाई है। चौधरी ने कहा कि 2021 में जयनारायण यूनिवर्सिटी की

जमीन के दो टुकड़े करके एमबीएम विश्वविद्यालय खोला गया। उसका कोई नया तुक नहीं था

कांग्रेस विधायक ने कहा- बीजेपी ने आदिवासी मंत्री को भी नहीं बख्शा

टोडाभीम से कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की बात करती हैं, लेकिन इन्होंने तो आदिवासी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को ही नहीं बक्शा। किरोड़ीलाल की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री नहीं सुनते। उन्हें अपने कामों के लिए मुख्य सचिव के पास जाना पड़ता हैं। मेहर ने मंत्री बाबूलाल खराड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आदिवासी मंत्री यहां बैठे हैं, लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मंत्री जी आप स्विच ऑफ हो गए हैं। आप सदन में एयरप्लेन मोड में बैठे रहते हो। आप ने एक भी शब्द नहीं बोला। आपके बगल में बैठे हुए मंत्री आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराने की बात कहते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा।

कांग्रेस विधायक ने की गहलोत राज में खुली यूनिवर्सिटी को बंद करने की मांग

कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने गहलोत राज में 2021 में जोधपुर में खोले गए एमबीएम यूनिवर्सिटी को बंद करने क मांग उठाई है। चौधरी ने कहा कि 2021 में जयनारायण यूनिवर्सिटी की जमीन के दो टुकड़े करके एमबीएम विश्वविद्यालय खोला गया। उसका कोई नया तुक नहीं था, इसे खोलते वक्त कुतर्क दिया गया कि इस यूनिवर्सिटी को सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र माण्डल में अवैध कोयला भट्टियों को अति शीघ्र ही ध्वस्त कर दिया जाएगा : पर्यावरण मंत्री

जयपुर(नि.सं.)। पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधान सभा क्षेत्र माण्डल में अति शीघ्र ही अवैध रूप से संचालित कोयला भट्टियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र माण्डल में संचालित अवैध कोयला भट्टियों के सम्बन्ध में भीलवाड़ा जिला प्रशासन के माध्यम से आश्वस्त किया गया है कि क्षेत्र में संचालित इन अवैध कोयला भट्टियों को अतिशीघ्र ही ध्वस्त कर क्षेत्र को इनसे मुक्त कर दिया जाएगा। इससे पहले विधायक श्री उदयलाल भडाणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र माण्डल में बिलानाम एवं चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियां संचालित थी। जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई है एवं शेष के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि निजी खातेदारी भूमियों पर अवैध कोयला भट्टियों के संबंध में सर्वे करवाया जा रहा है।

सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 4151 प्रकरणों में दी जा चुकी खातेदारी : राजस्व मंत्री

जयपुर(नि.सं.)। राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा ने शुक्रवार को राज्य विधान सभा में बताया कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में परियोजना क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र में अस्थाई काश्त (टी.सी.) भूमि व पुख्ता आवंटित भूमि के सम्बन्ध में गैर खातेदारी के कुल 5208 प्रकरणों में से 4151 प्रकरणों में खातेदारी दी जा चुकी है तथा 1057 प्रकरण लम्बित है। राजस्व मंत्री शून्यकाल में सूरतगढ़ विधायक श्री डूंगराम गेदर द्वारा इस सम्बन्ध में पर्ची के माध्यम से उठाये गए मामले पर जवाब दे रहे थे।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कलंदर के लिए एमबी प्रिन्टर्स एफ-76 करतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, बाईस गोदाम, जयपुर से मुद्रित व 03/156, ऋषि गालव नगर, गलता गेट जयपुर 302003 से प्रकाशित। फोन: 9891207447, 7062184621 संपादक: विजय कलंदर, उप संपादक -रूकमा शर्मा । समाचार चयन के लिए पीआरबी एट के तहत जिम्मेदार